

## संपादकीय

## खनन मार्फिया पर लगाम

## स्टांप इयूटी के साथ महंगाई का भी खर्च ध्यान

पंजाब सरकार ने स्टांप इयूटी बढ़ाकर और बालू खनन योजनाओं में परिवर्तन करके सरकार के लिए अधिक धन उपार्जन और बालू मार्फिया को नियंत्रित करने की योजना का संकेत दिया है। लगभग 17 कानूनी दस्तावेजों पर स्टांप इयूटी दोगुनी कर दी गई है। जैसे कि पावर ऑफ अटोर्नी, पार्टनरशिप डील, इडिमिनी बैंड और एफिडेविट इत्यादि। यह निर्णय सरकार की आमदनी और खर्च में आ रहे अंतर को भरने के लिए लिया गया है। सरकार को इससे लगभग 50 करोड़ की अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। चौथा 2018-19 के वित्तीय वर्ष की आधी अवधि बीत चुकी है तो उम्मीद की जाती है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 25 करोड़ की अतिरिक्त आय हो जाएगी। यद्यपि सरकार ने कहा है कि लगभग 8 वर्षों से इसमें कार्ड परिवर्तन नहीं किया गया था, अतः यह आवश्यक हो गया था परंतु इसमें एक मुद्दा विवादस्पद है कि प्रॉपर्टी द्रांजैवन को इससे बाहर रखा गया है जो कि रेवेन्यू का एक बड़ा साधन है। ऐसा लगता है कि सरकार रसूखदार लोगों को नाराज नहीं करना चाहती।

वैसे तो सरकार का खदान के व्यापार को पारदर्शी बनाने का कदम काफी सराहनीय है परंतु इस नई योजना में कई कठिनाई भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। खदानों की नीलामी प्रगतिशील बोली (प्रोग्रेसिव बिडिंग) प्री या से करना सरकार की आय का एक अच्छा ज्ञात है परंतु इसमें ग्राहकों के लिए बिल्डिंग मैटीरियल की कीमतें बहुत अधिक चुकाने की समस्या सामने आ रखी होती है। फिर कभी-कभी ऊंची बोली की वजह से खदान का ठेका लेने वाला बढ़ती जाती बोली के घलते माल की आपूर्ति नहीं कर पाता क्योंकि ऊंची बोली लगने के बाद उनके ग्राहक नहीं भिल पाते। इसलिए आपूर्ति की चेन टूट जाती है और इस चक्र र में बाजार में बालू-मोरंग के भाव काफी ऊंचे हो जाते हैं और यह भी नहीं सुनिश्चित होता कि बड़े बिजनेसमें इस तरह से व्यापार से बाहर हो जाएंगे। इस तरह की योजनाओं में परिवर्तन से किसी भी कार्य में बहुत सारे नियमों के लागू होने से अधिकारियों को खदान मालिकों से वसूली एक जरिया बन जाती है, जिससे मार्फिया कल्पन चालू रहता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन सब मालिकों में जागरूक रहेगी और समय के साथ अपनी नीतियों में उचित परिवर्तन करके इस क्षेत्र में ज्यादा सरल, सुविधाजनक और पर्यावरणरक्षक नियमों का अनुपालन करेगी।

## घर खरीदने के साथ कराएं बीमा, जरूर ध्यान रखें ये बातें

नई दिल्ली। नवरात्रि से दीपावली तक हेजारों लोग गाड़ी कर्माई खर्च कर घर खरीदते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसकी सुक्ष्मा का ध्यान नहीं देते। विशेषज्ञों का कहना है कि घर खरीदने के साथ उसका बीमा करकर भूकूप, आग जैसी आपाव या दुर्घटनाओं और सामान चोरी होने से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अगर किफायती हो तो बैंक से घर के लिए होम लोन लेते हैं, उससे भी बीमा करा सकते हैं।

## व्यापक बीमा प्लान बेहतर

एक कृप्रियेसिव (व्यापक) बीमा पॉलिसी में घर का ढांचा और सामान दायरे में होता है। पॉलिसीबाजार डॉट



कारोबारी अधिकारी तरुण माथुर का कहना है कि ग्राहक जरूरत के अनुसार, केवल मकान के ढांचे या केवल सामान का बीमा करा सकता है। चोरी, सेंधमारी के नुकसान के लिए भी

एडऑन ले सकते हैं। ऐसे लागत का आकलन करें

बीमा कंपनियां घर की लागत उस शहर में निर्भाय के खर्च और कारपेट एरिया का गुणाकर किमाली है।

लिहाजा आपका घर किस मंजिल पर है, इससे बीमा के प्रीमियम पर फर्क नहीं पड़ता।

कई तरह के जोखिम का कवर

कंपनियां होम इंश्योरेंस प्लान में 11 तरह के जोखिम कवर करती हैं। आग, बिजली, गैस या किसी अन्य घेरेल उपकरण में विस्फोट, विमान से नुकसान, क्रेन जैसी किसी मशीन से

हाउसहोल्ड पॉलिसी में गैराज में खड़ी गाड़ी दायरे में नहीं

गुप्त इंश्योरेस भी किकल्प

कई सारी सोसायटी के लिए बीमा कंपनियां खुद रुप पॉलिसी का भी विकल्प देती हैं। इसमें मकान का बीमा होता है और प्रयोक मकान मालिक अपनी विशेष जरूरतों के अनुसार कुछ और चीजें भी जुड़ा सकता है।

घर बेचे तो कपंनी को सूचित करें

आपको अपनी संपत्ति का बास्तविक मूल्य पता होना चाहिए। ब्रेकर की बजाय ऑनलाइन पॉलिसी खरीदना ज्यादा सस्ता। मकान में रह रहे शख्स का जीवन बीमा इसमें कवर नहीं। घर की मंजिल या ग्राउंड फ्लोर से प्रीमियम में अंतर नहीं। यहाँ मालिक चाहे तो पॉलिसी को चालू कर सकता है।

## कारोबारियों को मोदी सरकार ने दी राहत, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिला समय

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने कारोबारियों को बड़ी राहत दी है।

इसकी जानकारी में महीने का जीएसटीआर-



3बी अगले महीने की 20 तारीख तक

25 अक्टूबर तक

GSTR- 3B भर

पापै. इसके साथ ही

कारोबारी जुलाई 2017 से मार्च

2018 तक के Input Ta&

Credit (ITC) को भी 25

अक्टूबर तक क्लेम कर पापै.

वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल

बोर्ड ऑफ इंडियन टैक्सेस एंड

कस्टम्स (CBIC) ने एक ट्रॉट कर

करना

रिटर्न भरने को लेकर चिंता जारी है।

उहोने कहा था कि सेल्स रिटर्न और

सप्लायर्स द्वारा दाखिल किए जा रहे

पर्चेंज रिटर्न का मिलान करना

मुश्किल होगा। इसके चलते 20

तारीख तक जीएसटी रिटर्न फाइल

करना मुश्किल हो जाएगा।

जीएसटी रिटर्न को मोदी सरकार ने दी राहत, जीएसटी रिटर्न भरने के लिए मिला समय

## रुपये लीं सपाट शुरुआत, डॉलर के मुकाबले 73.30 के स्तर पर खुला

नई दिल्ली। इस कारोबारी हाफ्ते की रुपये ने

सपाट शुरुआत की है। सोमवार को रुपया

डॉलर के मुकाबले 73.30 के स्तर पर खुला

है। शुक्रवार के मुकाबले आज यह 2 पैसे की

बढ़त के साथ खुला है। इससे पहले शुक्रवार

को रुपया एक डॉलर के मुकाबले 73.32 के

स्तर पर बढ़ रहा था। 74.50 का आंकड़ा

पार करने के बाद रुपये में थोड़ी मजबूती

जरूर नजर आई है। हालांकि अभी कई

चुनौतियां इसके समाने खड़ी हैं।

बैंकेंक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में

उथल-पुथल ताजी है। इसके अलावा आगे

में बीजेपी सरकार पर सवाल उतारे हुए दावा

किया है कि केन्द्र सरकार का पेट्रोल-डीजल

की कीमत तय करने का बॉम्बूला गलत है,

जिसके चलते राज्य में डीजल को पेट्रोल से

अधिक कीमत पर बेचना मजबूरी हो गई है। गैरतलब है कि केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री

धर्मेंद्र प्रधान ऑडिशा से आते हैं और हाल

ही में पेट्रोल-डीजल पर केन्द्र सरकार द्वारा

बर्सूले जा रहे एक्साइज ड्यूटी में कटौती का

ऐलान करते हुए दर्शकों द्वारा जारी

प्रश्नों के साथ देखा जाएगा। इसके अलावा आंकड़ा

प्रधानमंत्री ने बोला जाएगा। ऑडिशा सरकार ने गवाहिनी के बाद रुपये में डीजल को बेचने के बाद रुपये में डीजल की कीमत बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जारी किया है।

बैंकों ने डीजल की कीमत बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जारी किया है।

बैंकों ने डीजल की कीमत बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जारी किया है।

बैंकों ने ड